

Telangana Today 23-June-2021

TS asks KRMB to stop AP projects

STATE BUREAU

Hyderabad

The Telangana State government has requested the Krishna River Management Board (KRMB) chairman, J Chandrashekhar Iyer to take immediate action to restrain Andhra Pradesh from carrying out works on Rayalaseema Pumping System and upgradation of Pothireddypadu Head Regulator, Banakacharla Complex to draw 80,000 cusecs from the foreshore of Srisailem reservoir and other related works.

Special Chief Secretary to Government (Irrigation and CAD Department) Dr Rajat Kumar, in a letter to Iyer, said these works were progressing at a brisk pace in violation of the NGT order and urged him to prevent il-



Works on the RLIS going on at brisk pace.

legal diversion of Krishna River waters.

"As you are aware, the NGT had directed the AP government not to go ahead with the execution of the RLIS without obtaining prior environmental clearance," he said. The NGT order dated February 24, 2021, directed that "the KRMB, on the basis of the

complaint made by the Telangana Government in this regard, are at liberty to go into the question and if it is found that there is any violation, they are at liberty to take appropriate action against the fourth respondent (AP) in accordance with law apart from the applicant to approach this tribunal at that stage." (SEE PAGE 2)

Telangana Today 23-June-2021

Further, the AP Chief Secretary submitted before the NGT that they were only doing the preparatory work for the Detailed Project Report and not the main work. It is pertinent to state that the tribunal held that “we are now believing the assertions made by the Chief Secretary that they are only doing the preliminary investigation for the purpose of preparing DPR.” In view of the same, it directed the board to send a fact-finding committee to ascertain the facts and take appropriate action against the State in case it was found that there was any violation of its orders by AP.

In this connection, the Engineer-in-Chief (General), Telangana had requested the board to act on the orders of NGT at the earliest and also to send a fact-finding committee to the project site to ascertain the status on the above subject and to take appropriate action. “We are constrained to note that the board has failed to ensure that the NGT orders are followed, as it is reliably learnt that AP is proceeding briskly with the construction of above work in utter violation of tribunal. Pictures that are attached with the letter depict the violation of NGT orders,” Rajat Kumar said in his letter.

It is evident from the pictures attached that by no stretch of imagination can the work going on at the site be said to be preliminary work required for the preparation of DPR.

“We are further constrained to note that there has been no action by the board is sending a fact-finding committee as directed by NGT,” Rajat Kumar said. The Council of Ministers of Telangana that met on June 19, 2021, expressed its strong displeasure over the illegal activities of the AP government in executing works of the RLIS in complete violation of the orders issued by authorities, to divert more than 80,000 cusecs of Krishna waters from Srisailem Reservoir to outside basin, depriving water to fluoride affected and acute drought-prone areas within Krishna basin of Telangana including Hyderabad drinking water supply.

As per Section-85(8)(d) of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, it is the responsibility of the board to restrain AP from proceeding with the illegal construction of RLIS works and enhancement of Srisailem Right Main Canal and other related works, he said.

In line with the same, the Ministry of Jalashakthi has already directed the AP government not to proceed with the project without submitting the DPR before the board and getting their appraisal done. “I once again request you take immediate and effective steps to stop this illegal activity of the AP government forthwith, and protect the genuine and legitimate claims of the people of Telangana on Krishna waters,” Rajat Kumar said.

Dainik Bhaskar 23-June-2021

सीएम भूपेश बघेल ने शुरू की गांवों के लिए जल जीवन मिशन योजना 19 हजार गांवों के 45 लाख घरों में मिलेगा पानी - घर-घर में लगेंगे फ्री नल कनेक्शन

भास्कर न्यूज़ | रायपुर

एक किलोमीटर दूर से पानी लाने की समस्या हुई दूर

प्रदेश में हरेक गांव में हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रदेश में 19 हजार 684 गांवों में 45 लाख 48 हजार परिवारों में पीने का साफ पानी पहुंचाया जाना है। अब तक केवल 5 लाख 69 हजार ग्रामीण परिवारों को ही इसका फायदा हुआ है। दरअसल यह केंद्र सरकार की योजना है। इसे 'जल जीवन मिशन' कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को मिशन से 16 जिले में 238 करोड़ 56 लाख 86 हजार रूपए की लागत के 658 कार्यों की शुरुआत की। इससे 65 हजार 396 घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने मिशन के प्रचार वाहन को खाना भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने की।

अब तक मिशन से 12.51 फीसदी परिवारों को ही नल से घरों में पानी मिल रहा है। मिशन के प्रारंभ होने के वक्त राज्य में 3 लाख 19 हजार ग्रामीण घरों यानी 7.0 प्रतिशत घरों में ही नल कनेक्शन था। इन 21 महीनों के दौरान राज्य में केवल 2 लाख 49 हजार जो करीब 5.49 प्रतिशत है, ग्रामीण घरों तक ही नल कनेक्शन पहुंचाए जा सका। यह धीमी गति के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राज्य को 'हर घर जल' बनने के लिए अभी शेष 39.78 ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचाना बाकी है। केंद्र सरकार ने इसमें तेजी लाने कहा है। छत्तीसगढ़ के 5 हजार 530 गांवों में कनेक्शन देने के लिए कार्य भी शुरू नहीं हुए हैं। राज्य ने 2021-22 के दौरान 22 लाख 14 हजार घरों में कनेक्शन देने की योजना बनाई। जबकि 2022-23 में 11 लाख 37 हजार घरों को तथा 2023-24 में शेष बचे 6 लाख 29 हजार घरों तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा।

बीजापुर के सुदूर अंचल का गांव कोतापाल की माताओं और बहनों को अब घर के लोगों के पीने का पानी लाने के लिए सर पे गुंडी और हडला धरकर एक-सवा किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता है। इस गांव के घरों में अब नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होने लगी है। राधा लिंगम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लाईव चर्चा के दौरान कहा कि आपने हमारे घरों में नल लगवाकर हमें बहुत सहुलियत दे दी है। अब हमें पेयजल के प्रबंध के लिए न तो दूर जाना पड़ता है, न ही समय खराब करना पड़ता है। बघेल का कोतापाल की सभी माताओं, बहनों और ग्रामीणों की ओर से



उनका आभार जताया। श्रीमती राधा लिंगम ने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि हैण्ड पम्प से पानी लाने के लिए लम्बी लाईन लगाना पड़ता था। अपने दुधमुंहे बच्चे को गोद में उठाकर पानी भरने जाती थी। इससे उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। श्रीमती राधा लिंगम ने

कहा कि अब सुबह-शाम नल से पानी आ जाता है। इससे सभी महिलाओं को सहुलियत होने लगी है। पानी भरने में जो समय खराब होता है, वह बचने लगा है, जिसे वह बच्चों की देखभाल और घर परिवार की अन्य जिम्मेदारियों में लगाने लगी है।

मुफ्त कनेक्शन देकर गांवों का सपना पूरा करेंगे : सीएम

सीएम ने कहा है कि प्रदेश के सभी 45 लाख 48 हजार ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2023 के अंत तक उनके घरों में मुफ्त नल कनेक्शन देकर पीने का साफ पानी देंगे। राज्य इस लक्ष्य को हर हाल में तय समय पर पूरा करेगा। इस साल राज्य बजट में 850 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इस साल 22 लाख से अधिक परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का काम पूरा कर लिया जाएगा।

योजना में केंद्र से मिले 445 करोड़

- 2020-21 में केन्द्रीय अनुदान के रूप में 445 करोड़ 52 लाख आबंटित।
- कार्यान्वयन की धीमी रफ्तार के कारण राज्य केवल 334 करोड़ 14 लाख रूपए करोड़ रूपए ही आहरित कर पाया।
- इस कारण उसे गांव-देहात के लिए जनसेवा के लिए 111 करोड़ 48 लाख रूपए लौटाने पड़े।
- राज्य के लिए केन्द्रीय आबंटन 1,908 करोड़ 96 लाख रूपए में से इस वित्त वर्ष में ही इस चार गुना वृद्धि की।
- राज्य को अगले पांच वर्षों यानी 2025-26 तक 3,402 करोड़ रूपए मिलेंगे।